संख्या	ब्लाक का नाम	जिला का
6.	बेतूल	बेतूल
7.	धर्मजयगढ़	रायगढ़
8.	अम्बिकापुर	सरगुजा
9.	आबूआ	आबूआ
10.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
11.	विजयराघवगढ़,	जबलपुर
12.	सियोनी	सियोनी
13.	अमरपाटन	सतना
14.	सिद्धि	सिद्धि
15.	शाहनगर	पन्ना
16.	कोटा	बिलासपुर
17.	छिदवाड़ा	छिदवाड़ा
18.	अब्दुल्लागंज	रायसेन
19.	बागली	देवास
20.	महो	इन्दौर
21.	बैरासिया	भोपाल
22.	गंजबसोदा	विदिशा
23.	मेहोरा	मेहोर
24.	नरसिंहगढ़	राजगढ़
25.	राहतगढ़	सागर
26.	दमोह	दमोह
27.	छतरपुर	छतरपुर
28.	काटंजी	बाल घाट
29.	दुरा	दुर्ग
30.	अभानपुर	रायपुर
31.	घाटीगांव	ग्वालियर
32.	पिछोरी	शिवपुरी
33.	चंदेरी	गुना
34.	कालपिप्पल	शाजपुर
35.	महिदपुर	उज्जैन
36.	मनासा	मन्दसौर
37.	बाघवा	खारगांव

सौर ऊर्जा की सहायता से सिंचाई

2416. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में और विशेषतया गुजरात में सौर ऊर्जा की सहायता से सिंचाई की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या फ्रांस ने इन प्रयोगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है ;

(घ) यदि हां, तो वे निबंधन और शर्तें क्या हैं जिनके तहत सहायता प्रदान की गई है ; और

(ङ) कार्यान्वित की जाने वाली प्रायोगिक परियोजनायें किस प्रकार की है ?

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने कृषि और संबंधित उपयोगों के लिए 200-1300 डब्ल्यू० पी० के बीच पी०वी० अरे क्षमता की 1000 सौर प्रकाशवोल्टीय जल पम्पन प्रणालियों के स्थापन के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान एक प्रदर्शन परियोजना शुरू की थी । परियोजना को बाजार अभिविन्यास के रूप में कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को सौंपी गई थी । इस योजना के तहत राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं । अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की वित्तीय सहायता से गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से छठी और सातवीं योजना के दौरान माइक्रो सिंचाई सहित विभिन्न जल पम्पन आवश्यकताओं के लिए गुजरात में 300-360 डब्ल्यू०पी० की 98 सौर प्रकाशवोल्टीय जल पम्पन प्रणालियों स्थापित की गई हैं।

(ग) से (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ गांवों में 50 सौर

पी०वी० पम्पों की संस्थापना के लिए भारत–फ्रांसीसी जल संसाधन सहयोग कार्यक्रम के तहत "ग्रामीण क्षेत्रों में लघु सिंचाई और जल आपूर्ति पर आधारित सौर ऊर्जा हेतु एक प्रायोगिक परियोजना" का प्रस्ताव किया गया है । फ्रांस सरकार ने प्रायोगिक परियोजना के लिए 2.00 मिलियन फ्रांसीसी फ्रांक का अनुदान और 3.8 मिलियन फ्रांसीसी फ्रांक का ऋण (कुल 2.96 करोड़ रुपए के समतुल्य) प्रदान करने का प्रस्ताव किया है । प्रयोगिक परियोजना का उद्देश्य सामुदायिक प्रबंधन के माध्यम से छोटे और सीमान्तिक किसानों को लाभ पहुंचाना है ।

Import *of* waste from *U&A*

2417. SHRI AJIT P. K. JOGI: SHRI RAM GOPAL. YADAV:

Will the PRIME MINISTER, be pleased to state;

(a) whether Government propose to import waste from the USA for generation of power on project Hazel near Kochi;

(b) if so, the norms to decide the kind of waste to be imported;

(c) whether there is a possibility of environmental hazard as a result of the project;

(d) if so_ the details thereof; and

(e) the steps taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATS IN THE MINISTRY QP NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): *(a)* There >s no such proposal before the Government.

(b) *ta (e)* 0oes not arise-

Guidelines to State Govemments regarding Non-Conventional Energy

2418. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY; WiH the PRIME MINIS. TER be pleased to state:

(a) whether Government have issued model guidelines to State Gov-eminent suggesting ways in which non-conventional energy can be brought by SEBs;

(b) if so_ the details of the guidelines;

(c) whether State Govemments have agreed to cooperate in implementing these goidelines: and

(d) if so, the deiails; thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OP NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) and (b) A set of guidelines has been forwarded to all the States towards a uniform policy pertaining to private sector power projects based *on* Non-Conventional Energy Sources. The guidelines include incentives and facilities for wheeling, banking, third party sale and buy-back of electricity generated by the Non-Conventional Energy Sources at a minimum rate of Rs. 2.25 per unit by the State Electricity Boards.

(c) artd (d) Policies have already been announced by Punjab, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh based on these guidelines. Policies in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala have been modified to in-corporate some of the suggestions. Certain policies have also bee$_n$ announced by Gujarat and Karnataka. The matter is being pursued with other States.